दैनिक भारत कि

तामीर

संपादक - काझी मकदूम शफीउद्दीन hinditameer@gmail.com

Editor in chief- Qazi makhdoom shafiuddin

बीड (महाराष्ट्र) | वर्ष-२ ला | अंक-२३ वा | शनिवार २० सितम्बर २०२५ | RNI TITLE CODE:MAHHIN11405/120/1/3/2024 | किमत : २ रूपये | पन्ने - ४

सरकार के जीआर के कारण मराठवाड़ा जल उठा है और ओबीसी समाज में अशांति: विजय वडेट्टीवार

जमीर काझी, मुंबई: राज्य सरकार द्वारा निकाले गए जीआर के कारण ओबीसी समाज का नुकसान हो रहा है। ओबीसी उपसमिति के सदस्य होने वाले वरिष्ठ मंत्री छगन भुजबळ और पंकजा मुंडे बाहर एक भूमिका रख रहे हैं, वही भूमिका उन्हें बैठक में रखनी चाहिए। ओबीसी विरोधी इस शासन निर्णय को कौन रद्द करेगा, कब करेगा ऐसा सवाल कांग्रेस विधिमंडळ नेता विजय वडेट्टीवार ने उठाया है।

शुक्रवार को मीडिया से बात करते हुए वडेट्टीवार ने छगन भुजबळ पर टीका की। जरांगे पाटील के आंदोलन को समर्थन देने वालों को गिराएं ऐसा आवाहन भुजबळ कर रहे हैं तो फिर सरकार ही गिरानी चाहिए, ओबीसी आरक्षण पर गदा लाने वाला शासन निर्णय ही सरकार ने निकाला है। उस मंच पर सरकार के प्रतिनिधि के रूप में मंत्री गए थे। एक तरफ भुजबळ मुख्यमंत्री की प्रशंसा करेंगे दूसरी तरफ टीका करेंगे यह दोहरा चरित्र है। ओबीसी आरक्षण को अगर धक्का नहीं लगता तो सरकार सभी नेताओं को बुलाए चर्चा करे फिर हम प्रमाण देंगे ओबीसी का क्या नुकसान हो रहा है, ऐसा कहकर वडेट्टीवार ने कहा कि, 'महायुति सरकार द्वारा निकाले गए शासन निर्णय के कारण मराठवाड़ा जल उठा है ओबीसी बनाम मराठा फिर विवाद बढ़ा है। स्कूलों से विद्यार्थियों को निकाला जा रहा है। पडळकर ने जो टीका की वह मां को गाली देने जैसी है। राजनीतिक नेताओं पर टीका करें लेकिन उनके माता-पिता पर बोलना अनुचित है, महाराष्ट्र की राजनीति में यह पहली बार हो रहा है। पडळकर किसके इशारे पर बोल रहे हैं, कौन उन्हें पीछे से समर्थन दे रहा है? ऐसा सवाल कांग्रेस विधिमंडळ नेता वडेट्टीवार ने उठाया।

अतिरिक्त जानकारी और संदर्भ

यह बयान महाराष्ट्र में हाल ही में जारी किए गए सरकारी(जीआर) से संबंधित है, जो मराठा आरक्षण के लिए कुणबी प्रमाणपत्र जारी करने पर केंद्रित है। इस जीआर ने ओबीसी आरक्षण को कमजोर करने की आशंका पैदा की है, जिससे मराठवाड़ा में तनाव बढ़ा है और ओबीसी-मराठा समुदायों के बीच संघर्ष फिर से भड़क उठा है।कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने आरोप लगाया है कि यह निर्णय समुदायों के बीच नफरत फैला रहा है, और स्कूलों से छात्रों को निकालने जैसी घटनाएं हो रही हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट ने हाल ही में इस जीआर के खिलाफ दायर एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें ओबीसी हितों को खतरे का हवाला दिया गया था।छगन भुजबळ जैसे ओबीसी नेता इस मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, और युवाओं में आत्महत्या की घटनाएं बढ़ने की चिंता जताई जा रही है यह विवाद मराठा आंदोलनकारियों जैसे मनोज जरांगे पाटील के समर्थन से जुड़ा है, जो ओबीसी कोटा में मराठाओं को शामिल करने की मांग कर रहे हैं।

वडवणी के ईदगाह व कब्रिस्तान की ज़मीन से अतिक्रमण हटाने की जाएगी कार्रवाई

वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष समीर काज़ी का आश्वासन

काज़ी अमान/बीड़

बीड़ ज़िले के वडवणी स्थित ईदगाह और कब्रिस्तान की १४ एकड़ २२ गुंठे ज़मीन वक्फ बोर्ड की मिल्कियत होने का फ़ैसला छत्रपति संभाजीनगर (औरंगाबाद) के वक्फ ट्रिब्यूनल ने दिया है। अदालत के निर्णय के अनुसार सोमवार से इस अतिक्रमण को हटाने के लिए क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह आश्वासन महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्ड के ज़िम्मेदार और सक्रिय अध्यक्ष समीर काज़ी ने वडवणी की मुस्लिम बिरादरी को दिया। इस अवसर पर पूर्व नगर उपाध्यक्ष फ़ारूक पटेल, एआईएमआईएम के ज़िलाध्यक्ष एडवोकेट शेख शफ़ीक भाई, खलील पठान समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे।

१९ सितंबर २०२५ को शुक्रवार की नमाज़ के बाद दोपहर में बीड़ ज़िले के वडवणी के मुस्लिम भाइयों ने महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्ड के

अध्यक्ष समीर काज़ी से उनके कार्यालय में मुलाक़ात की और वडवणी के ईदगाह व कब्रिस्तान की १४ एकड़ २२ गुंठे ज़मीन पर हुए अतिक्रमण को वक्फ ट्रिब्यूनल के फ़ैसले के अनुसार हटाने की मांग की।

समीर काज़ी को दिए गए लिखित निवेदन में कहा गया कि वडवणी के गट नंबर २१९ में १४ एकड़ २२ गुंठे ज़मीन पर प्राचीन काल से मुस्लिम समाज का ईदगाह और कब्रिस्तान है और यह ज़मीन वक्फ बोर्ड की मिल्कियत है। लेकिन इस ज़मीन पर कई लोगों ने क़ब्ज़ा कर रखा है, साथ ही ग़ैरक़ानूनी रूप से कुछ सरकारी दफ़्तर भी बनाए गए हैं। इस ज़मीन का दावा छत्रपति संभाजीनगर (औरंगाबाद) के वक्फ ट्रिब्यूनल में लंबित था। इस मुक़दमे में वक्फ ट्रिब्यूनल ने ज़मीन वक्फ बोर्ड की मिल्कियत होने का फ़ैसला सुनाया है।

वडवणी में मुस्लिम समाज की आबादी बड़ी संख्या में है और बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए यह इलाक़ा काफ़ी नहीं है। पहले से यहाँ बड़ी संख्या में क़ब्रें मौजूद हैं। सिर्फ़ एक से डेढ़ एकड़ खाली ज़मीन पर ईदगाह है, जहाँ मुस्लिम बिरादरी ईद की नमाज़ अदा करती है। इस एक से डेढ़ एकड़ को छोड़कर बाक़ी सारी ज़मीन पर अतिक्रमण हो चुका है। अगर यह अतिक्रमण हटा दिया जाए तो मुस्लिम बिरादरी को दफ़न के लिए यह ज़मीन इस्तेमाल करने का अवसर मिलेगा। इसलिए अतिक्रमण हटाने की मांग निवेदन में की गई है।

बीड़ ज़िले के वडवणी के ईदगाह और कब्रिस्तान की १४ एकड़ २२ गुंठे ज़मीन वक्फ बोर्ड की मिल्कियत होने का फ़ैसला छत्रपति संभाजीनगर (औरंगाबाद) के वक्फ ट्रिब्यूनल ने दिया है। अदालत के निर्णय के अनुसार सोमवार से इस अतिक्रमण को हटाने के लिए क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह आश्वासन महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्ड के ज़िम्मेदार और सक्रिय अध्यक्ष समीर काज़ी ने वडवणी की मुस्लिम बिरादरी को दिया। इस अवसर पर पूर्व नगर उपाध्यक्ष फ़ारूक पटेल, एआईएमआईएम के ज़िलाध्यक्ष एडवोकेट शेख शफ़ीक भाई, खलील पठान समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित थे।

लाड़ली बहन योजना के लिए वेबसाइट पर ई-केवाईसी सुविधा शुरू-मंत्री आदिती तटकरे

मुंबई -जमीर काजी

मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण योजना में पारदर्शिता लाने और लाभार्थियों को नियमित रूप से आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से https://ladakibahin.maharashtra.gov.in इस आधिकारिक वेबसाइट पर ई-केवाईसी (e-KYC) की सुविधा शुरू कर दी गई है।

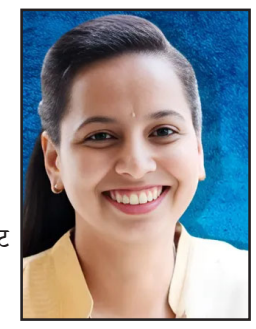

महिला एवं बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे ने जानकारी देते हुए कहा कि यह प्रक्रिया मोबाइल फोन के माध्यम से भी सरलता से की जा सकती है और अगले दो महीनों में सभी लाभार्थियों को यह प्रक्रिया पूर्ण करने का आग्रह किया गया है। उन्होंने बताया कि इस प्रक्रिया से भविष्य में अन्य शासकीय योजनाओं का लाभ लेने में भी मदद मिलेगी।

महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने, उनके स्वास्थ्य और पोषण में सुधार करने तथा परिवार में उनकी निर्णायक भूमिका को मजबूत करने के लिए राज्य सरकार मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण योजना लागू कर रही है। इस योजना के माध्यम से सीधे लाभ हस्तांतरण (Direct Benefit Transfer) द्वारा आर्थिक सहायता दी जाती है।

महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से ई-केवाईसी के माध्यम से लाभार्थियों का आधार प्रमाणीकरण किया जाएगा। यह प्रक्रिया बेहद आसान और सरल है तथा महिलाएं इसे स्वयं अपने मोबाइल से भी पूरी कर सकती हैं। साथ ही तटकरे ने यह भी स्पष्ट किया कि लाभार्थियों को किसी प्रकार की उलझन में नहीं आना चाहिए और यदि कोई व्यक्ति आर्थिक मांग करता है तो उसकी बातों में नहीं आना चाहिए।

मुख्यमंत्री ने फिर से विधायक पडळकर के कान खींचे!

आपत्तिजनक बयान को लेकर पूरे राज्य में गुस्सा

जमीर काझी

मुंबई, : भाजपा के विवादास्पद विधायक गोपीचंद पडळकर ने राष्ट्रवादी शरद पवार गुट के वरिष्ठ नेता जयंत पाटील के बारे में दिए गए गंदे बयान पर शुक्रवार को पूरे राज्य में गुस्सा व्यक्त किया गया। खुद राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी इसकी नोटिस ली और इस मामले में पडळकर के कान फिर से सार्वजनिक रूप से खींचे। उनका बयान अनुचित और असमर्थनीय है और सार्वजनिक जीवन में व्यवहार करते समय हमें क्या बोलना है इसका ध्यान रखना चाहिए, ऐसे शब्दों में सुनाया।

इस बीच, पडळकर के इस बयान के विरोध में सांगली सहित पूरे राज्य में विभिन्न स्थानों पर मोर्चा, आंदोलन करके निंदा की गई। सभी पार्टियों के नेताओं ने इस बारे में नाराजगी व्यक्त की।

पडळकर के बयान के बारे में मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि, उनका बयान अनुचित है। किसी के पिता या परिवार के बारे में ऐसे बयान देना उचित नहीं है। इस बारे में मैंने उनसे बात की है, सुझाव दिया है। इस बारे में मुझे शरद पवार का भी फोन आया था। उन्हें बताया कि ऐसे प्रकार के बयान का हम भी कभी समर्थन नहीं करेंगे।

ऐसा कहकर वे बोले कि,

पडळकर एक युवा, बहुत आक्रामक नेता हैं। कई बार आक्रामकता दिखाते समय अपने बोलने का सटीक अर्थ क्या

निकलेगा यह ध्यान में नहीं आता, और इसलिए उन्हें बताया गया है कि यह ध्यान में रखकर ही बयान देना चाहिए। आपको भविष्य में एक अच्छे नेता के रूप में बड़ी संभावना है। बोलते समय क्या विचार निकलेंगे, इसका विचार करना चाहिए, ऐसा मैंने सलाह दी है, ऐसा उन्होंने बताया।

पडळकर ने क्या कहा था?

पडळकर ने जत में बोलते हुए, जयंत पाटील पर गंदे शब्दों में टीका की थी। यह बिनअक्ल इंसान है। हम उनके जैसे भिखारी की औलाद नहीं हैं। यह राजारामबापू पाटील की औलाद नहीं होगी। कुछ गड़बड़ है, ऐसी स्तर छोड़कर टीका पडळकर ने की थी।

शरद पवार की मुख्यमंत्री से नाराजगी

पडळकर के विकृत बयान के बारे में राष्ट्रवादी कांग्रेस के संस्थापक अध्यक्ष शरद पवार ने आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को फोन करके नाराजगी व्यक्त की। ऐसी गंदी भाषा का उपयोग करना उचित नहीं है, ऐसे लोगों को रोका जाना चाहिए, ऐसे शब्दों में पडळकर की निंदा की गई है।

अतिरिक्त जानकारी और संदर्भ

यह घटना महाराष्ट्र की राजनीति में हालिया विवाद से जुड़ी है, जहां भाजपा विधायक गोपीचंद पडळकर ने जत रैली में एनसीपी (एसपी) नेता जयंत पाटील के माता-पिता पर आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिसे भिखारी की औलाद जैसे शब्दों से जोड़ा गया।शरद पवार ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से फोन पर बात की और इस तरह की भाषा को अस्वीकार्य बताते हुए कार्रवाई की मांग की।फडणवीस ने पडळकर की निंदा की, उन्हें युवा और आक्रामक नेता बताते हुए सलाह दी कि बोलते समय सावधानी बरतें, और पुष्टि की कि उन्होंने पडळकर से बात की है।इस बयान के खिलाफ सांगली और अन्य जगहों पर विरोध प्रदर्शन हुए, और सभी दलों के नेताओं ने नाराजगी जताई।पडळकर की यह दूसरी ऐसी घटना है, जहां उनकी भाषा पर सवाल उठे हैं

उर्दू दैनिक तामीर के २५ वे साल में क़दम रखने पर एक और पेशकश

मुख्यमंत्री फडणवीस चुनाव आयोग की दलाली बंद करें-हर्षवर्धन सपकाल

जमीर काजी

मुंबई, : लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने वोट चोरी के बारे में सबूत दिए हैं, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के पास गृह विभाग भी है, उनके पुलिस ने राजुरा विधानसभा में वोट चोरी के मामले में अपराध दर्ज किया है फिर भी फडणवीस चुनाव आयोग की दलाली कर रहे हैं, उन्हें यह दलाली बंद करनी चाहिए। ऐसी आलोचना कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन पाटिल ने शुक्रवार को की।

दादर स्थित कांग्रेस भवन में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा, मराहुल गांधी ने चुनाव आयोग द्वारा की जा रही वोट चोरी को सबूतों के साथ उजागर किया है। इसके बारे में चुनाव आयोग कोई स्पष्टीकरण नहीं दे सकता। इसलिए भाजपा की कमर में आग लग गई है। आयोग कुछ नहीं बोलता। लेकिन भाजपा के नेता इसके

लिए क्यों आगे आते हैं?, यह स्पष्ट होना चाहिए। मुख्यमंत्री फडणवीस ने वोट चोरी करके सत्ता हासिल की है। इसलिए वे चोर मुख्यमंत्री हैं, उन्हें चुनाव आयोग की दलाली बंद करके अपने पास मौजूद गृह विभाग की जिम्मेदारी ईमानदारी से निभानी चाहिए, ऐसा भी उन्होंने कहा।

वरिष्ठ नेता जयंत पाटिल के बारे में भाजपा विधायक गोपीचंद पडळकर द्वारा किए गए बयान पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि, पहले सुसंस्कृत, सभ्य, विचारवान और कवि साथ में होते थे लेकिन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कुछ निकम्मे और विकृत लोग साथ रखे हैं। जयंत पाटिल के बारे में किया गया बयान यह बेलगामपन की पराकाष्ठा है और फडणवीस लाचार और अधर्मी मुख्यमंत्री हैं।

आरएसएस को संविधान उपहार में देंगे

महात्मा गांधी की जयंती के दिन दो अक्टूबर को विजयादशमी पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को १०० वर्ष पूरे हो रहे हैं और यह नियति का एक संकेत है। १०० वर्ष पूरे करने वाले रा. स्व. संघ ने अब तो नाथूराम और विषाक्त विचार छोड़कर समता, बंधुता और सामाजिक न्याय के संविधान तथा गांधी विचारों को स्वीकार करना चाहिए, इसके लिए उन्हें संविधान की प्रति उपहार में देंगे, ऐसा कहते हुए सपकाल ने कहा, मसंविधान मनुस्मृति पर आधारित होना चाहिए, ऐसी रा. स्व. संघ की अपेक्षा थी, गोलवलकर ने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर को ऐसा पत्र भेजा था। लेकिन हम विशेष लोग यह संघ का विचार है जबकि संविधान का विचार यह हम भारत के लोग ऐसा है। गोलवलकर का बंच ऑफ थॉट्स यह रा. स्व. संघ और भाजपा का बाइबल है। संविधान को नकारने वाला विचार भाजपा का है। स्वतंत्रता के बाद पचास वर्ष रा. स्व. संघ ने अपने कार्यालय पर राष्ट्रध्वज तिरंगा भी नहीं फहराया था। अब सौ वर्ष होने पर संघ ने विषाक्त और जहर भरे विचार छोड़कर संविधान के विचार को स्वीकार करना चाहिए, ऐसा कहते हुए उन्होंने कहा,फ

कांग्रेस पार्टी की हमेशा संविधान की रक्षा करने की भूमिका रही है। महात्मा गांधी के पौत्र तुषार गांधी के पहल पर २८ सितंबर से २ अक्टूबर के दौरान संविधान सत्याग्रह यात्रा का आयोजन किया गया है। नागपुर की दीक्षाभूमि से शुरू होकर सेवाग्राम तक जाएगी।

भाजपा नगरसेवकों का कांग्रेस में प्रवेश

पनवेल महानगरपालिका के भाजपा नगरसेवक हरिश केणी, रविकांत म्हात्रे, कैलास घरत ने अपने सहयोगियों के साथ आज कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल की उपस्थिति में कांग्रेस पार्टी में प्रवेश किया। कांग्रेस तालुका अध्यक्ष पद के लिए साक्षात्कार टिळक भवन दादर में कांग्रेस तालुका अध्यक्ष पद के लिए निरीक्षकों द्वारा सिफारिश किए गए उम्मीदवारों के साक्षात्कार लिए गए। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल, विधिमंडळ कांग्रेस पार्टी के नेता विजय वडेट्टीवार, कांग्रेस वर्किंग कमिटी के सदस्य सांसद चंद्रकांत हांडोरे, नसीम खान, गोवा के प्रभारी माणिकराव ठाकरे, अखिल भारतीय कांग्रेस कमिटी के सचिव बी. एम. संदीप, यु. बी. व्यंकटेश, प्रदेश उपाध्यक्ष संगठन और प्रशासन ड गणेश पाटील उपस्थित थे।

जनता का पैसा जनता के लिए या सरकारी बाबुओं को सुविधा पहुँचाने के लिए?

छत्रपति शिवाजी महाराज चौक से राजुरी वेस तक सड़क का नाम किसी भी सरकारी दफ़्तर में दर्ज नहीं, तो फिर सड़क का काम कौन कर रहा है?-अमरजान पठान

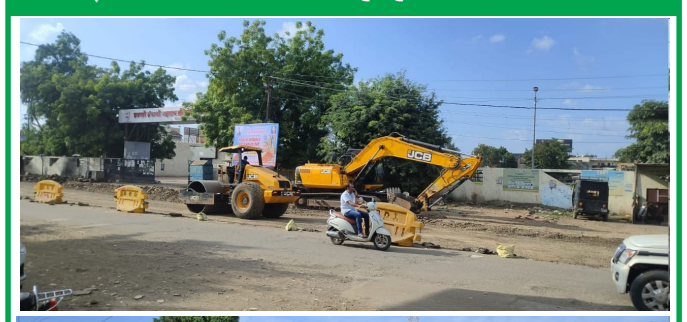

बीड़ / प्रतिनिधि

छत्रपति शिवाजी महाराज चौक से राजुरी वेस तक सड़क का नाम किसी भी सरकारी कार्यालय के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है, फिर सड़क का काम कौन कर रहा है? सड़क और उसके लिए निधि स्वीकृत न होने के बावजूद यदि छत्रपति शिवाजी महाराज चौक से ज़िला परिषद गेट तक सड़क का काम हो रहा है, तो जनता का पैसा जनता के लिए ख़र्च हो रहा है या फिर सरकारी बाबुओं को सुविधा पहुँचाने के लिए? - यह सवाल महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के बीड़ शहराध्यक्ष अमरजान पठान ने प्रशासन के सामने रखा है।

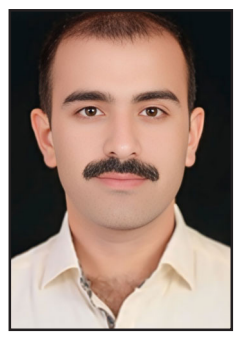

विस्तृत जानकारी के अनुसार, बीड़ शहर के छत्रपति शिवाजी महाराज चौक से बशीरगंज, राजुरी वेस, कारंजा रोड, बलभीम चौक, पुराना बाज़ार से कोतवाल वेस तक सड़क का काम तुरंत शुरू करने की मांग को लेकर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की ओर से बीड़ नगर परिषद कार्यालय व ज़िलाधिकारी कार्यालय को लिखित निवेदन देकर कई बार विरोध प्रदर्शन और आंदोलन भी किए गए। इसके बावजूद बीड़ नगर परिषद की ओर से लिखित जवाब दिया गया कि छत्रपति शिवाजी महाराज चौक से बशीरगंज राजुरी वेस तक की सड़क उनके कार्यक्षेत्र में नहीं आती।

इस पत्र का संज्ञान लेकर जब अमरजान पठान ने ज़िला परिषद कार्यालय, सार्वजनिक निर्माण विभाग और राष्ट्रीय राजमार्ग कार्यालय में भी निवेदन दिया, तो वहाँ से भी लिखित उत्तर मिला कि छत्रपति शिवाजी महाराज चौक से बशीरगंज राजुरी वेस तक की सड़क उनके विभागीय रिकॉर्ड में नहीं है।

यदि किसी भी सरकारी विभाग के रिकॉर्ड में इस सड़क का नाम नहीं है, तो फिर छत्रपति शिवाजी महाराज चौक से ज़िला परिषद कार्यालय गेट तक हो रहे सड़क कार्य को कौन कर रहा है? अब तक बनी सड़क का निधि किसने उठाया? बिना मंज़ूरी के ठेकेदार किसके आदेश पर या किस अधिकारी के दबाव में

मुस्लिम समाज को शिक्षा में ५% आरक्षण तुरंत लागू करने की मांग

मुंबई – मुस्लिम वेल्फेअर असोसिएशन की उपाध्यक्ष तस्नीमा शेख ने उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार को ज्ञापन सौंपकर मुस्लिम समाज के शिक्षा में ५% आरक्षण को तुरंत लागू करने की मांग की है।

ज्ञापन में कहा गया है कि हाल ही में मराठा समाज को आरक्षण का लाभ देने के लिए राज्य सरकार ने तातडी और दृढ़ इच्छाशक्ति दिखाते हुए रास्ता निकाला, जो स्वागत योग्य है। लेकिन न्यायालय द्वारा स्वीकृत होने के बावजूद मुस्लिम समाज को शिक्षा में आरक्षण देने के लिए सरकार ने आज तक ठोस पावले नहीं उठाए, यह अत्यंत खेदजनक है।

तस्नीमा शेख ने कहा कि स्वतंत्रता के बाद से ही विभिन्न आयोगों और समितियों ने मुस्लिम समाज की प्रगति के लिए, विशेषकर शिक्षा और नौकरी के अवसरों में, आरक्षण की सिफारिश की है। माननीय न्यायालय ने भी शिक्षा क्षेत्र में मुस्लिम समाज के लिए ५% आरक्षण को मंजूरी दी है। इसके बावजूद इसे अब तक लागू न करना मुस्लिम समाज के साथ अन्याय है।

उन्होंने चेतावनी दी कि मुस्लिम समाज आंदोलन की राह पर जाना नहीं चाहता, लेकिन अगर मजबूरी में आंदोलन करना पड़ा तो हालात अलग मोड़ भी ले सकते हैं। इसलिए सरकार को चाहिए कि इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए मुस्लिम समाज को न्याय दिलाए और शिक्षा में ५% आरक्षण तुरंत लागू करे।

आज बीड़ के जुना बाज़ार में मज़दूर सेना कार्यालय और हिंद मल्टी सर्विस सेंटर के कार्यालय का भव्य उद्घाटन संपन्न हुआ। इस अवसर पर हिंद मल्टी सर्विस के मालिक नवेद ख़ान उर्फ़ (बाबा ख़ान) ने समाजसेवी मुसा ख़ान पठान का शाल, हार और पुष्पगुच्छ देकर सम्मान किया। इस मौके पर उनके साथ जैद क़ादरी भी नज़र आए।

सरकार के मजदूर विरोधी फैसले पर श्रमिक संगठनों की चुप्पी क्यों?

कम से कम बीड़ जिले की यूनियनों को आगे आना चाहिए–एस.एम.युसूफ़

बीड़ (प्रतिनिधि) – सरकार ने हाल ही में मजदूर विरोधी नीति अपनाते हुए यह निर्णय लिया है कि श्रमिकों को रोज़ाना १२ घंटे की एक ही शिफ्ट में काम करना होगा। इस फैसले का टीवी चैनलों के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार हुआ, लेकिन श्रमिक संगठन इस ओर पूरी तरह से उदासीन दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में कम से कम बीड़ जिले की श्रमिक यूनियनों को इस फैसले का विरोध करना चाहिए, ऐसा आह्वान स्वतंत्र पत्रकार एस.एम. युसूफ़ ने किया है।

जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि कंपनियों और कारखानों में मजदूरों को पहले से ही एक टार्गेट दिया

जाता है और उस हिसाब से वे खून-पसीना बहाकर काम पूरा करते हैं। आठ घंटे की शिफ्ट में ही मजदूर पूरी तरह थक जाते हैं, बावजूद इसके कई कंपनियां निजी ठेकेदारों और दलालों के माध्यम से अस्थायी मजदूरों की भर्ती कर उनसे बिना किसी सुविधा दिए १२ घंटे तक काम करवा रही थीं। अब तो स्वयं सरकार ने आधिकारिक तौर पर १२ घंटे की शिफ्ट लागू करने का निर्णय लिया है। इससे कंपनियां मजदूरों से सस्ते दामों पर गुलामों की तरह काम कराएंगी और शिक्षित बेरोजगार युवा शोषण का शिकार होंगे।

युसूफ़ ने आगे कहा कि रोज़ाना १२ घंटे काम करने के बाद मजदूर आधे मरे-थके हुए कंपनियों से बाहर निकलेंगे और अपने परिवार के सुख-दुख में भी शरीक नहीं हो पाएंगे। रोज़ाना टार्गेट के मुताबिक १२ घंटे मेहनत करना कोई आसान काम नहीं है। अगर सरकार को इस कठिनाई का अंदाज़ा नहीं है तो नेताओं को खुद मजदूर बनकर कंपनियों में कम से कम एक महीने काम करना चाहिए, तभी उन्हें समझ आएगा कि मजदूर किन हालात में काम करते हैं।

उन्होंने सवाल उठाया कि यदि यह बात सरकार और प्रशासन की समझ में नहीं आ रही, तो क्या राजनीतिक दलों से जुड़ी यूनियनें और स्वतंत्र श्रमिक संगठन भी सो गए हैं या मैनेज हो गए हैं? अब तक किसी भी संगठन ने सरकार के इस मजदूर विरोधी फैसले का विरोध क्यों नहीं किया? क्या श्रमिक संगठनों की ताक़त और धमक खत्म हो गई है?

इस पृष्ठभूमि में युसूफ़ ने अपील की कि कम से कम बीड़ जिले की श्रमिक यूनियनों को आगे आकर सरकार के इस मजदूर विरोधी फैसले का विरोध करना चाहिए और इसे रद्द करवाना चाहिए।

राज्य सरकार ने ८०,९६२ करोड़ रुपये के समझौते किए

नौ कंपनियों से ४०,३०० रोजगार के अवसर

मुंबई (विशेष प्रतिनिधि) –

गोरगांव में एआईआईएफए (खखऋ-) आयोजित स्टील महाकुंभ कार्यक्रम में महाराष्ट्र शासन के उद्योग विभाग ने नौ कंपनियों के साथ कुल ८०,९६२ करोड़ रुपये के सामंजस्य करार (चेण) पर हस्ताक्षर किए। सरकार का दावा है कि इन समझौतों से राज्य में ४०,३०० रोजगार का सृजन होगा।

इन परियोजनाओं के तहत गडचिरोली, चंद्रपुर, नागपुर, वर्धा, रायगढ़, छत्रपति संभाजीनगर (औरंगाबाद), सातारा आदि जिलों में नए प्रकल्प (प्रोजेक्ट) शुरू किए जाएंगे।

गडचिरोली – सुमेध टूल्स प्रा. लि. और हरिओम पाइप इंडस्ट्रीज लिमिटेड के संयुक्त प्रकल्प से ५,१३५ करोड़ रुपये का निवेश होगा और ५,५०० रोजगार उपलब्ध होंगे।

छत्रपति संभाजीनगर (औरंगाबाद) -

NPSPL एडवांस्ड मटेरियल (अथा ग्रुप) प्रा. लि. की ओर से ५,४४० करोड़ रुपये का निवेश कर क्रिटिकली एडवांस्ड लिथियम बैटरी मटेरियल और कार्बन कॉम्प्लेक्स की स्थापना होगी। इससे ५,००० रोजगार की उम्मीद है।

वर्धा – रश्मी मेटलर्जिकल इंडस्ट्री प्रा. लि. का २५,००० करोड़ रुपये का एकीकृत स्टील प्रकल्प शुरू होगा, जिससे १२,००० रोजगार सृजित होंगे।

रायगढ़ – जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड का ४१,५८० करोड़ रुपये का स्टेनलेस स्टील प्रकल्प बनेगा, जिससे १५,५०० रोजगार मिलेंगे।

इसके अलावा अन्य जिलों में भी निवेश होगा –चंद्रपुर – आइकॉन स्टील इंडिया प्रा. लि. ८५० करोड़ रुपये निवेश कर स्पंज प्रकल्प लगाएगी, जिससे १,५०० रोजगार होंगे।

सातारा (वाई) – फिल्ट्रम ऑटोकॉम्प प्रा. लि. १०० करोड़ रुपये निवेश कर ऑटोमोटिव स्टील पार्ट्स का प्रकल्प लगाएगी, जिससे १,२०० रोजगार बनेंगे। चंद्रपुर (मूल) – जी. आर. कृष्णा फेरो अलॉय प्रा. लि. स्पंज प्रकल्प में १,४८२ करोड़ रुपये का निवेश करेगी और ५०० रोजगार देगी।

नागपुर – जयदीप स्टीलवर्क इंडिया प्रा. लि. आईएसपी प्रकल्प हेतु १,३७५ करोड़ रुपये निवेश करेगी, जिससे ६०० रोजगार का अवसर होगा।

इन करारों से राज्य में भारी निवेश आकर्षित होने के साथ-साथ हजारों युवाओं को रोजगार मिलने की संभावना है।

दैनिक भारत की तामीर अखबार के मालिक, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक काजी मखदूम शफीउद्दीन ने आरएम प्रिंटरर्स, बार्शी रोड, बीड 431122 महाराष्ट्र में मुद्रित कर के दैनिक तामीर, नगर परिषद परिसर, बशीर गंज, बीड, महाराष्ट्र कार्यालय से प्रकाशित किया है। मोबाइल : 9270574444 ईमेल : hinditameer@gmail.com वेबसाइट : www.dailytameer.com

daily Bharat ki tameer newspaper owner printer publisher editor Quazi makhdoom shafiuddin has printed at RM printers barshi road beed 431122 Maharashtra at published at office daily tameer nagar parishad complex Bashir gunj beed Maharashtra. Mobile : 9270574444 Email : hinditameer@gmail.com Website : www.dailytameer.com